भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3092
मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/श्रावण17, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के लिए डाटाबेस

3092. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':
श्री धर्मेन्द्र कश्यपः
श्री हरीश द्विवेदी :
श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो सहकारी डाटाबेस तैयार करने में शामिल किए गए बिंदुओं/मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसकी तैयारी हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ग) सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में डाटाबेस तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(घ) उक्त डाटाबेस नीति निर्माताओं और सहकारी क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए किस प्रकार सहायक होगा;
(ङ) क्या राज्य सरकार और अन्य हितधारक उक्त डाटाबेस का उपयोग करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) उक्त डाटाबेस को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा और वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाएगा; और
(छ) उक्त डाटाबेस को तैयार करने के बाद सहकारी समितियों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (छ): सहकारिता मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित कर रहा है। चरण-I के तहत, तीन सेक्टर यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी हो चुकी है। चरण- II के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों व फेडरेशन का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण-III के तहत, डेटाबेस को अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत शेष सहकारी समितियों तक बढ़ाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के निर्माण के दौरान, सभी स्तरों पर हितधारकों के साथ परामर्श के कई दौर आयोजित किए गए हैं, जिनमें प्राथमिक से लेकर शीर्ष इकाइयाँ अर्थात् राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें, राष्ट्रीय सहकारी संघ, नियामक निकाय आदि को शामिल किया गया । सहकारी समितियों से संबंधित सामान्य जानकारी यानी स्थान विवरण, सदस्यों की संख्या, आर्थिक गतिविधियां इत्यादि के अलावा, डेटाबेस में संबंधित सेक्टर की सेक्टर-विशिष्ट और विभिन्न स्तर पर कार्यरत सहकारी समितियों में आपसी व्यवसायिक संबंधों की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस देश भर के विभिन्न सेक्टर की सभी सहकारी समितियों पर प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी को एकल बिंदु पर प्रदान करना है। डेटाबेस सहकारी क्षेत्र में नीति निर्माण, प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों के भौगोलिक वितरण में अंतर और प्राथमिक सहकारी समितियों एवं शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में आपसी संबंधों की पहचान करने में भी मदद करेगा। डेटाबेस को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा बनाए गए एक सुरक्षित मंच के माध्यम से 24x7 आधार पर सभी हितधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य पंजीयक (RCS) के जिला-स्तर पंजीयक कार्यालयों द्वारा डेटाबेस के नियमित अद्यतनीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SoP) भी तैयार की गई हैं।

*****